भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1833
10/02/2026 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि उत्पादकता और सिंचाई क्षमता

1833. श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेलः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि उत्पादकता और सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई विशेष परियोजना कार्यान्वित कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट जिलों में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ख) जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, बुंदेलखंड क्षेत्र सहित देश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य कृषि भूमि तक पानी की वास्तविक पहुंच बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना है। पीएमकेएसवाई के एआईबीपी (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम) घटक के तहत, बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंहपुर, सिंध चरण II, बरियारपुर एलबीसी और अर्जुन सहायक नामक चार सिंचाई परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। अर्जुन सहायक परियोजना, जिससे बांदा सहित विभिन्न जिलों को लाभ मिल रहा है, ने 57.64 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया है।

इसके अलावा, बुंदेलखंड क्षेत्र में पीएमकेएसवाई के जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार (आरआरआर) घटक 'हर खेत को पानी' (एचकेकेपी) का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है। बांदा जिले की तीन योजनाओं सहित झांसी, महोबा, बांदा और ललितपुर जिलों में 20 आरआरआर-जल निकाय योजनाएं लागू की जा चुकी हैं, जिनसे 2.35 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है।

बुंदेलखंड क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से "केन-बेतवा इंटरलिंकिंग परियोजना" भी शुरू की गई है, जिसका लक्ष्य उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों में 2.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई क्षमता प्राप्त करना है।

इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग वर्ष 2015-16 से बुंदेलखंड क्षेत्र सहित पूरे देश में केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) 'प्रति बूंद अधिक फसल' (पीडीएमसी) लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई, अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से कृषि स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है। वर्ष 2015-16 से अब तक, बुंदेलखंड क्षेत्र में पीडीएमसी के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई द्वारा 2.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है, जिसमें बांदा जिले में 28571 हेक्टेयर और चित्रकूट जिले में 25725 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है।

कृषि उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाने और उसे सतत बनाए रखने के लिए, भारत सरकार राज्य सरकारों के जरिए विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं जैसे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, राष्ट्रीय दलहन मिशन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, बीज ग्राम कार्यक्रम, परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय तिलहन मिशन, समेकित बागवानी विकास मिशन, बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि मशीनीकरण उप-मिशन और कृषि विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता सहित उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश भर में किया जा रहा है। तथापि, केंद्रीय स्तर पर इन योजनाओं की प्रगति से संबंधित जिलावार जानकारी नहीं रखी जाती है।

****